सरकारी उपेक्षा से घटी औद्योगिक विकास की रफ्तार : सालुंखे

प्रदूषण आदि के चलते मुंबई में सेवा एवं वित्तीय क्षेत्र में कामकाज शुरू करने वालों को लाइसेंस मिल रहा है, लेकिन उत्पादन में लगी कंपनियों को मदद नहीं दी जा रही है. जो कंपनियां कामकाज का विस्तार चाहती हैं उन्हें सरकारी मदद एवं रियायतें मिलनी चाहिए. मुंबई एवं उसके आसपास के क्षेत्र में यदि उत्पादन गतिविधियां ठप होती हैं तो बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होंगे, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और मुंबई धीरे-धीरे अपना आर्थिक राजधानी होने का वजूद खो देगी.

मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन सरकारी उपेक्षा के चलते यहां की औद्योगिक गतिविधियां धीरे-धीरे घटती जा रही हैं. कभी मुंबई को औद्योगिक गतिविधियों का केन्द्र माना जाता था, लेकिन सरकारी नीतियों, जमीन की बढ़ती कीमतों, महंगा लेबर और सेवा एवं वित्तीय क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने के कारण कंपनियां अपना उत्पादन आधार मुंबई से हटाकर अन्यत्र ले जाने पर मजबूर हो रही हैं.

वर्ष 1995 के बाद से मुंबई के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में काफी तेजी आई. सड़कों को चौड़ा करना, नई सड़कों का निर्माण, सड़कों का सीमेंटीकरण, पादचारी एवं उड़ानपुलों का निर्माण, मिलों की जगह ऊंची-ऊंची इमारतों, मल्टीप्लैक्स शॉपिंग मालों का निर्माण नई-नई टाऊनशिप का विकास आदि मुंबई की प्रगति तो दर्शाते हैं, लेकिन इस विकास की दौड़ में महाराष्ट्र शासन एवं मनपा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को जैसे भूल से गए.

स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस डेवलमेंट चेंबर ऑफ इंडियन और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (आईआईटीसी-इंडिया) के अध्यक्ष चंद्रकांत सालुंखे का कहना है कि मुंबई में 60000-65000 सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग हैं. इन उद्योगों में 50 से 60 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है. यदि हम देखें तो आयकर, सेवाकर, वैट, उपकर एवं शिक्षा कर के रूप में अकेले मुंबई से सरकार को कुल कर संग्रह का 40-45 प्र.श. हिस्सा प्राप्त होता है. इसमें 60-70 प्र.श. योगदान लघु एवं मध्यम उद्योगों का है.

इतने बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्योगों को सरकार की ओर से विशेष रियायतें एवं सहूलियतें नहीं मिल पा रही हैं. अंधेरी एमआईडीसी की तरह निजी इंडस्ट्रियल इस्टेट में स्थापित उद्योगों को भी पानी, बिजली एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलना चाहिए.

सालुंखे ने कहा कि औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक बड़ी बाधा ऑक्ट्राय है. ऑक्ट्राय के कारण अनेक उद्योग-धंधे मुंबई के बाहर जा रहे हैं. कंपनियां मुंबई में कार्पोरेट कार्यालय भले ही रखें, लेकिन उनकी उत्पादन गतिविधियां मुंबई के बाहर जा रही हैं. सरकार को इसे रोकने के लिए ऑक्ट्राय को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए.

प्रदूषण आदि के चलते मुंबई में सेवा एवं वित्तीय क्षेत्र में कामकाज शुरू करने वालों को लाइसेंस मिल रहा है, लेकिन उत्पादन में लगी कंपनियों को मदद नहीं दी जा रही है. जो कंपनियां कामकाज का विस्तार चाहती हैं उन्हें सरकारी मदद एवं रियायतें मिलनी चाहिए. मुंबई एवं उसके आसपास के क्षेत्र में यदि

उत्पादन गतिविधियां ठप होती हैं तो बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होंगे, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और मुंबई धीरे-धीरे अपना आर्थिक राजधानी होने का वजूद खो देगी.

मुंबई को कास्मोपोलिटन महानगर बताते हुए सालुंखे ने कहा कि यहां भाषा, प्रांत एवं जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए. सभी जाति, धर्म एवं भाषा के लोगों को व्यवसाय करने की छूट होनी चाहिए. किसी भी शहर की आर्थिक प्रगति केवल एक वर्ग द्वारा संभव नहीं है. जहां तक मुंबई में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की बात है तो हम 10 वर्ष पीछे चल रहे हैं. मेट्रो रेल जिस पर अब काम हो रहा है, उसे काफी पहले शुरू कर दिया जाना चाहिए था. सालुंखे ने कहा कि ट्रैफिक समस्या पर निजात पाने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए. बोरीवली से नरीमन पाइंट तक पहुंचने के लिए बांद्रा-वर्ली सी-लिंक का विस्तार होने के साथ-साथ जलमार्ग से भी परिवहन शुरू किया जाना चाहिए.

मेट्रो रेल को मुंबई के हर कोने तक पहुंचाया जाना चाहिए. एसी बसें और बढ़ाई जानी चाहिए ताकि लोग निजी कारों की जगह इनका उपयोग करें. इससे ट्रैफिक समस्या कम होगी. लोगों में ट्रैफिक नियमों के अनुपालन की आदत डालने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए. पार्किंग के लिए पे एंड पार्क की व्यवस्था हर स्थानों पर होनी चाहिए.

मुंबई में पर्यटन के लिए अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन दुखद बात है कि सरकार ने मुंबई में दर्शनीय स्थलों का विकास नहीं किया है. सरकार को चाहिए कि देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई दर्शनीय पाइंट बनाए. मुंबई को साफ-सुथरा रखने के लिए वेस्टर्न व ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे सहित प्रमुख स्थानों पर सुलभ शौचालय जैसे शौचालय बनें. मुंबई के विकास में तभी तेजी आ सकती है जब विकास की गतिविधियों को देखने के लिए एक समर्पित मंत्रालय बनाया जाए. लघु एवं मध्यम उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए भी काम किया जाना चाहिए. पानी की समस्या हल करने के लिए एक दूरगामी नीति बनाने की जरूरत है. मुंबई में सेवा, वित्त, इलेक्ट्रॉनिक, डायमंड, इंजीनियरिंग आदि उद्योगों के लिए ऊंची संभावनाएं हैं.